E-CONTENT

Subject : Economics
Class : B.A Part II (Paper IV)
Topic : Redemption of Public Debt
(सार्वजनिक ऋण लौटाने की विधियाँ)

By:
EKATA KUMARI
Guest Faculty
(Assistant Proffesor)
Mahila College Sasaram; Rohtas
Email I'd:
bhardwajekata@gmail.com

विद्वानों ने सार्वजनिक ऋण चुकाने के कई तरीकों का उल्लेख किया है। "सार्वजनिक ऋण अपेक्षाकृत आधुनिक घटना है तथा विश्व प्रजातंत्रीय सरकारों के विकास के साथ व्यवहार में आया है।" यह परिभाषा जे. के. मेहता के अनुसार दिया गया है।

सार्वजनिक ऋण; राज्य द्वारा आय प्राप्त करने का एक साधन है। लोक अथवा सार्वजनिक ऋण उस ऋण को कहते हैं जिसे कि राज्य अपनी प्रजा से अथवा अन्य देशों के नागरिकों से लेता है। सरकार जब उधार लेती है तो उससे लोक ऋण का जन्म होता है। डाल्टन के अनुसार "सार्वजनिक अधिकारियों की आय प्राप्त करने का एक ढंग सार्वजनिक ऋण भी है।" एडम स्मिथ के अनुसार "सार्वजनिक ऋण से युद्ध एवं फिजूलखर्ची जैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं।"

इस प्रकार सार्वजनिक ऋण में दो प्रकार से कमी की जा सकती है :—

(i) ऋण निषेध
(ii) ऋण का भुगतान

(i) ऋण निषेध :—

इसका आशय है कि ऋण के भुगतान करने से इनकार करना। यह एक ऐसी प्रणाली है,

जिसमें सरकार ऋण के भार को नहीं मानती है और मूल धन तथा ब्याज देने से इनकार कर देती है। यह नीति आंतरिक एवं बाह्य दोनों तरह की ऋणों के संबंध में अपनाई जाती है। विश्व के इतिहास में रूस, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस आदि देशों द्वारा यह कहानी दुहराई जा चुकी है।

किंतु नैतिक दृष्टि से ऋण निषेध का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष इसी नीति का समर्थन नहीं किया जा सकता है। क्योंकि इससे मौद्रिक क्षेत्र में सरकार की साख समाप्त हो जाती है और आगे ऋण लेने का मार्ग बंद हो जाता है। देश की राजनीतिक स्वतंत्रता खतरे में पर सकती है। इसी प्रकार आंतरिक ऋणों को इनकार करने से देश के अंदर अशांति फैल जाती है और कभी-कभी क्रांति की भी संभावना हो जाती है। प्रजातांतरिक सरकार के प्रति जनता के प्रतिकूल होने का भय होता है। इसलिए ऋण के भार को कम करने के लिए उसे चुका देना ज्यादा शांतिपूर्ण और उचित तरीका है। सार्वजनिक ऋण को चुकाने की मुख्य नीतियाँ नीम्न है :-

(a.) पूर्ण भुगतान :-

ऋण चुकाने का यह सबसे अच्छा तरीका है। इसमें ऋण की अवधि पूरा होने पर ~~मुल~~ मूल धन के साथ-साथ ब्याज भी चुका दी जाती है। इसमें सरकार की साख बनी रहती है और भविष्य में ऋण लेना आसान रहता है।

(b.) **वार्षिक वृत्ति :-**

इस विधि के अंतर्गत सरकार दीर्घकालीन या ~~स्थायी~~ स्थाई ऋणों का भुगतान वार्षिक किस्तों में नियमित रूप से करती है अर्थात् सरकार ब्याज सहित मूल धन की राशि को एक निश्चित मात्रा लौटाती रहती है।

इसमें ऋण की राशि धीरे-धीरे कम हो जाती है और एक निश्चित अवधि के बाद पूर्णतया समाप्त हो जाती है। इस प्रणाली का समर्थन गोल्ड स्टोन (Gold Stone) ने किया है।

(c.) **ऋण परिवर्तन :-**

इस नीति में सरकार वर्तमान ऋणों का वास्तव में भुगतान नहीं करती बल्कि पुराने ऋणों को नये ऋणों में परिवर्तन कर देती है। इस विधि में ऋणों की शर्तों एवं ब्याज की दरों में परिवर्तन कर दिया जाता है। ऐसी प्रणाली निम्नलिखित दो कारणों से अपनाई जाती है :-

1. ऋण भुगतान की अवधि आ जाने पर सरकार भुगतान करने में समर्थ नहीं हो पाती है।

2. जब वर्तमान ब्याज दरें पुराने दर से कम है।

यद्यपि इस विधि में वर्तमान ऋण भार ~~में~~ कम हो जाता है। लेकिन भावि ऋण

भार में आवश्यक वृद्धि हो जाती है। इसी आधार अधिकांश विद्वानों ने भुगतान की इस विधि का समर्थन नहीं किया है। डाल्टन ने ऋण रूपांतरण को ऋण प्रबंध की एक अत्यंत कमजोर विधि माना है तथा 'अनुचित वित्त व्यवस्था' कह कर इसकी आलोचना की है।

(d) ऋण परिशोधन :—

ऋण के भुगतान का यह एक नियमित, सुव्यवस्थित, शांतीपूर्ण, प्रभावशाली एवं सार्वजनिक प्रचलित तरीका है। यही कारण है कि इसका सबसे ज्यादा समर्थन किया जाता है। इस विधि का जन्मदाता इंग्लैंड का वॉलपॉल नामक विद्वान माना जाता है। इसलिए इन्हें father of sinking fund कहा जाता है।

इस नीति के अंतर्गत ऋण भुगतान करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा एक कोष का निर्माण किया जाता है तथा इस कोष में प्रतिवर्ष सार्वजनिक आय में से बचाकर कुछ धन राशि रख दी जाती है तथा उससे ही ऋण पर ब्याज और मूल धन का भुगतान किया जाता है।

कोष का निर्माण दो तरह से किया जाता है :—

1. सरकार की वार्षिक आय में से
2. नये ऋण लेकर कोष में डाल कर।

आजकल कोष की स्थापना अधिकतर

सरकार की वार्षिक आय में से ही की जाती है। डा॰ डाल्टन ने परिशोधन कोष को दो भागों में विभाजित किया है :—

1. निश्चित परिशोधन कोष
2. अनिश्चित परिशोधन कोष।

पहले प्रकार के कोष मे सरकार प्रतिवर्ष एक निश्चित रकम जमा करती रहती है। जबकि दूसरे प्रकार के कोष में वह तभी धनराशि जमा करती है। जब उसे अपने वार्षिक वित्तीय बजट मे कुछ अतीरिक्त प्राप्त होता है। यह राशि बजट में बचत होने पर निर्भर करती है।

सरकार द्वारा निश्चित परिशोधन कोष की स्थापना नीम्नलिखित तीन आधारों पर की जाती है :—

1. पहले तरीके के अंतर्गत तो कोष में प्रतिवर्ष जितनी रकम जमा की जाती है, उससे प्राप्त ब्याज भी कोष में जमाकर दिया जाता है। इस प्रकार कोष की मात्रा तेजी से बढ़ती जाती है तथा अंत में ऋण का भुगतान कर दिया जाता है।

2. दूसरे तरीके के अंतर्गत सरकार कोष की राशि से प्राप्त ब्याज को प्रतिवर्ष ऋणदाताओं में बाँटती रहती है तथा इस भुगतान की मात्रा बराबर बनी रहती है।

3. तीसरे तरीके के अंतर्गत सरकार प्रतिवर्ष कोष की रकम पर ब्याज की राशि से भी अधिक राशि का भुगतान ऋणदाताओं को करती जाती है। तथा इस तरह भुगतान की मात्रा घटती रहती है।

प्रो. जे. के. मेहता ने ऋण परिशोधन कोष का समर्थन करते हुए लिखा है कि "ऋण परिशोधन कोष की पद्धति ऋण शोधन का सर्वोत्तम तरीका है। यह एक क्रमबद्ध प्रणाली है तथा कोई भी इसे किसी विशेष ऋण की आवश्यकताओं की पूर्ति में समायोजित कर सकता है।"

(e.) लॉटरी द्वारा भुगतान :—

इस विधि में ऋणों का भुगतान लॉटरी के आधार पर किया जाता है तथा जिस व्यक्ति का नंबर उना जाता है। उसी को ऋण का भुगतान कर दिया जाता है। इस रीति का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें ऋण दाता को ऋण मिलने के निश्चित समय का पता नहीं रहता है।

(f.) क्रमानुसार भुगतान :—

इस विधि के अनुसार ऋण का भुगतान क्रम के अनुसार किया जाता है। इसमें जो ऋण पहले प्राप्त होते हैं, उनका भुगतान पहले ही कर दिया जाता है। इस प्रकार ~~प्र~~ की विधि में प्रत्येक ऋण का कुछ भाग प्रतिवर्ष परिपक्व हो जाता

है। इस विधि का प्रयोग अमेरिका में स्थानीय सरकारों द्वारा किया जाता है।

(g.) <u>पूंजी कर :—</u>

पूंजी कर भी भुगतान करने का एक तरीका है। पूंजी कर अस्थाई ऋण भार को कम करने की दृष्टि से बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। युद्धकालीन ऋणों को भार से मुक्ति पाने हेतु अनेक देश की सरकारों ने इस विधि का प्रयोग किया है।

यह वह कर है जो व्यक्तियों की संपत्ति तथा आय के ऊपर लगाया जाता है। जिसका आधार प्रगतिशील होता है। सर्वप्रथम संपत्ति की न्यूनतम कर रहित सीमा निर्धारण कर देती है और इस सीमा से ऊपर वाले प्रत्येक व्यक्ति पर बढ़ती हुई दरों से करारोपण किया जाता है।

निःसंदेह पूंजी का ऋण शोधन का एक क्रांतिकारी तरीका है, लेकिन इसका प्रयोग अधिकांशतः अनुत्पादक ऋणों जैसे - युद्ध संबंधी ऋणों के लिए अधिक किया जाता है। पूंजी कर के समर्थकों में रिकार्डो, पीगू, हैण्डरसन, एजवर्थ, लॉरेंस आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इसके विरुद्ध में जोसिया स्टाम्प, श्रीमती उरशाला हीक्स, पेन आदि हैं (Plan).।

पूंजी कर के पक्ष में नीम्न लिखित तर्क दिये जाते हैं। जो इस प्रकार है :-

1. पूंजी कर द्वारा हम ऋण से मुक्त हो जाते हैं, जिससे भावी कर भार में कमी आजाती है।

2. पूंजी कर समाज में व्याप्त आय एवं संपत्ति के वितरण की विषमता को दूर करने में सहायक होता है।

3. पूंजी कर से मुद्रा - स्फीति मे कमी आती है।

4. पूंजी कर के रूप में ऋणों का भुगतान शीघ्रता एवं सरलता पूर्वक किया जा सकता है।

5. ऋणों के भार से मुक्त हो जाने पर उद्योगों एवं व्यापार पर भारी मात्रा में कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती उसका विकास सुचारु रूप से होता रहता है।

6. कर भार के मुक्त होने पर सरकार अपनी अधीकाधिक मात्रा में समाज कल्याण पर खर्च कर सकती है और देश के विकास में योगदान दे सकती है।

7. चूंकि युद्धकाल में सर्वाधिक लाभ पूंजीपति वर्ग करता है, इसलिए पूंजी कर के रूप में आर्थिक सेवा लेना सर्वथा उचित एवं न्यायपूर्ण है।

पूंजी कर के विरुद्ध में भी कर दिये जाते हैं जो निम्न हैं :-

1. पूंजी कर को लगाने पर नागरिकों की कार्य करने, बचत करने की इच्छा एवं शक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

2. पूंजी कर को लगाने से देश की पूंजी विदेशों की ओर जाने लगती है। जिसका देश के आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

3. पूंजी कर से जनता में अविश्वास पैदा हो जाता है। देश में विनियोग कर्ता विनियोग करने से डरने लगते हैं।

4. पूंजी एवं संपत्ति का सही-सही मूल्यांकन करने में अनेक व्यवहारिक कठिनाईयाँ खड़ी हो जाती है।

5. पूंजी कर अन्यायपूर्ण है क्योंकि यह कम उपभोग करने वाले तथा बचत करने वालों पर एक दण्ड के समान है।

<u>श्रीमती उरसला हीक्स</u> ने लिखा है कि " पूंजी कर देश की अर्थव्यवस्था के शरीर के ऊपर एक operation के समान है, जिससे या तो रोगी मर ही जाएगा या फिर अच्छा ही हो जाएगा। "